इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 1 अगस्त 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सू ाी

मौद्रिक नीति ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
सूक्ष्मवित्त -- ----------5
विदेशी मुद्रा विनिमय----------5
अंतरराष्ट्रीय समा ाार----------5
अर्थव्यवस्था ----------6
उत्पाद एवं गंठ ाोड----------6
नयी नियुक्तियां----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी ाानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समा ाार----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सू ाना / समा ाार की मदें सार्व ानिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो ुकी / ुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए ा रही / रहे हैं। उक्त सू ाना / समा ाार की मदों में व्यक्त किए गए वि ाार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समा ाार मदों / घटनाओं अथवा ि ास किसी भी प्रकार की सू ाना की स ाई
अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

1- मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा 26 ुलाई 2011

मौद्रिक उपाय

- ालनिधि समायो ान सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद दर में तात्कालिक प्रभाव से 50 आधार अंकों की वृद्धि, ाो 7.5 % से ब . कर 8% हो गई।

- ालनिधि समायो ान सुविधा के तहत प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद दर 100 आधार अंक के अंतर सहित पुनर्खरीद दर के स्तर पर नियत, ाो 7 % पर स्वयमेव समायोि ात।

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 100 आधार अंक के अंतर सहित पुनर्खरीद दर से अधिक स्तर पर नियत, ाो तात्कालिक आधार पर 9% पर पुन: अंशाकित।

- अनुसूि ात बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) उनकी निवल मांग और सावधि देयताओं
  (NDTL) के 6 % पर कायम रखा गया।

घरेलू अर्थव्यवस्था

- ूंकि अनुसूि ात वाणि ियक बैंकों ने उनकी ामा दरें ब .ा दी हैं, उन्हें इसका प्रत्युत्तर ामाराशियों में ब .ोत्तरी के रूप में मिला, ाो अप्रैल 2011 की शुरूआत में वर्षानुवर्ष 17.4 % से ब . कर ुलाई 2011 में 18.4 % हो गईं। इसके साथ ही इसी अवधि में मुद्रा वृद्धि 18.4 % से घट कर 15.0 % हो गई। अ ाछी ामा वृद्धि की पृष्ठभूमि में

वर्षानुवर्ष व्यापक मुद्रा (एम 3) की आपूर्ति में ुलाई 2011 के प्रारंभिक दिनों में रि र्व बैंक के 16 % के निर्देशात्मक प्रक्षेप-पथ को पीछे छोड़ते हुए 17.1 % की वृद्धि द र्ा हुई।

- 1 ुलाई 2010 से लागू की गई आधार दर प्रणाली ने उधार दरों में पारदर्शिता ब ा दिया है और बैंकों की उधारदायी दरों को मौद्रिक नीति स्पंदनों के प्रेषण का अधिक सुविज्ञ मूल्यांकन करने में भी समर्थ बनाया है। ुलाई 2010 से बैंकों की मॉडल आधार दर में 225 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। कम ालनिधि वाली स्थितियों के साथ मिल कर ऋण मूल्य-निर्धारण की आधार दर प्रणाली ने मौद्रिक प्रेषण प्रक्रिया की शक्ति और पारदर्शिता, दोनों को ही ब ा दिया है।

- वर्ष 2011-12 में ालनिधि की स्थितियां नीतिगत दृष्टिकोण के अनुरूप सामान्य रूप से अब तक कमी वाले रूप में कायम रही हैं। इस अवधि में 22 ुलाई तक ालनिधि समायो ान सुविधा (LAF) पटल के माध्यम से ालनिधि का औसत दैनिक निवल निषे ान लगभग 48,000 करोड़ रुपये था, ाो निवल मांग एवं ावधि देयताओं के 1% के भीतर ही था।

मौद्रिक समु ाय

- मुद्रा आपूर्ति (M3) और ऋण वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्तियां रिज़र्व बैंक के सांकेतिक प्रक्षेप-पथ से अधिक के स्तर पर कायम रहीं। उभरती वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011-12 की एम 3 वृद्धि के सांकेतिक अनुमान को अधोमुखी रूप में संशोधित करके उसे 3 मई के नीतिगत वक्तव्य में यथा-वर्णित 16.0% से घटा कर 15.5% कर दिया गया है। खाद्येतर बैंक ऋण से सम्बन्धित अनुमान में भी अधोमुखी संशोधन करते हुए उसे 19.9% से घटा कर 18.0% कर दिया गया है।

मुख्य घटनाएं

19 बैंक अधिकारियों के लिए सा ाी परीक्षा लेंगे

19 सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में से किसी भी एक में अधिकारी बनने के आकांक्षियों को अब 18 सितम्बर को अपने ंग की पहली सा ाी लिखित परीक्षा (CWE)

देनी होगी। बैंकिंग कार्मिक ायन संस्थान (IBPS) ने सहभागी बैंकों की ओर से उक्त सा ाी परीक्षा की सू ाना दे दी है। उक्त परीक्षा के अंक एक वर्ष तक वैध होंगे।

ग्राहक अधिकाधिक रूप से एटीएमों, मोबाइलों पर 'बैंक' करने लगे

मैककिंसी की इंडिया पर्सनल फाइनैन्सियल सर्विसे ा सर्वेक्षण 2011 के अनुसार भारतीय ग्राहक बैंकिंग लेनदेनों के लिए एटीएम, इंटरनेट और मोबाइल का अधिकाधिक रूप से उपयोग कर रहे

हैं। कुल लेनदेनों में इन वैकल्पिक ैनलों का अंश बैंक शाखाओं की तुलना में निरंतर ब. रहा है। वर्ष 2007 में 1% की तुलना में भारत में बैंकिंग उपभोक्ताओं के लगभग 7% अब इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं। तदनुसार, इसी अवधि में शाखा के उपयोग में 15% की कमी आई है।

एटीएम से सम्बन्धित विवादों का निवारण 7 दिनों में

एटीएम से सम्बन्धित शिकायत का 7 दिनों के भीतर निवारण न किए ाने पर बैंक को प्रति दिन संभाव्य रूप से 100 रुपये का नुकसान उठाना होगा। 1 ुलाई, 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने एटीएम से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के अनिवार्य समय को पहले के 12 दिनों से घटा कर एक सप्ताह कर दिया है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

वाणि ियक स्थावर संपदा परियो ानाओं को ऋण देने में धीमापन बरतें

परिसम्पत्ति की कीमतों में अस्थिरता से भयभीत हो कर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से वाणि ियक स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण देने में धीमापन बरतने के लिए कहा है। पिछले एक वर्ष में वाणि ियक स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार देने में तीव्र वृद्धि हुई है और उक्त क्षेत्र में अन ार्क आस्तियों की वृद्धि समग्र ऋण ाूकों में हुई वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक बनी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वाणि ियक स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार में पिछले वर्ष की 1.2% की तुलना में 20% की वृद्धि परिलक्षित हुई है। स्थावर संपदा क्षेत्र की कीमतों में गिरावट आ ाने पर बैंकों को आस्ति की गुणवत्ता के सम्बन्ध में गंभीर दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

मुद्रा प्रतिरक्षण ोखिम सम्बन्धी नये मानदंड

व्यापारिक लेनदेनों में रुपये के अधिकाधिक प्रयोग को सुगम बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवासी आयातकों और निर्यातकों को भारत से किए ाने वाले निर्यातों और भारत में किए ाने वाले आयातों के सम्बन्ध में भारतीय रुपयों में बी ाकीकृत उनके मुद्रा ोखिम को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I वाले बैंकों के पास प्रतिरक्षित (hedge) कराने की अनुमति दे दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक इन लेनदेनों के लिए परि ालनात्मक दिशानिर्देश पहले ही ारी कर ुका है। इस प्रतिरक्षण की रकम और अवधि को अन्तर्निहित लेनदेनों की रकम से अधिक नहीं होने दिया ाएगा तथा उन्हें आवधिक भुगतान अथवा प्राप्त होने वाली राशियों की वसूली से सम्बन्धित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप रखना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रोत्साहन

कम बैंक वाले रा यों के कम बैंक वाले ि ालों में टियर-3 से टियर-6 तक के केन्द्रों में खोली ाने वाली प्रत्येक शाखा के लिए किसी बैंक को टियर -1 अथवा टियर-2 वाले केन्द्र में एक शाखा खोलने के लिए प्राधिकृत किया ाएगा। बैंकों को दिया ाने वाला यह प्रोत्साहन अधिक समरूप स्थानिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन रा यों में अधिक शाखाएं खोले ाने की निरंतर आवश्यकता की पृष्ठभूमि में लिया गया है।

बैंकिंग ागत की घटनाएं

1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी की सू ाना सीबीआई को दें

बैंकिंग धोखाधड़ियों पर शिकं ा कसने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों से 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधडियों के मामलों की सू ाना शीघ्रतापूर्वक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को तथा उससे कम की रकमों की पुलिस को देने के लिए कहा है। नि ाी और विदेशी बैंकों से 1 लाख रुपये और उससे अधिक रकम से सम्बन्धित मामलों की सू ाना पुलिस को देने के लिए कहा गया है। कर्म ारियों द्वारा की गई 10,000 रुपये से अधिक की धोखाधड़ियों की सू ाना भी पुलिस को दी ानी ाहिए। इसके अतिरिक्त, 7.5 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वाले मामलों की सू ाना सम्बन्धित केन्द्रों के बैंकिंग सुरक्षा और धोखाधड़ी कक्ष, ाो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आर्थिक अपराध स्कंध का विशिष्टीकृत कक्ष है, को दी ानी ाहिए। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना ाहिए कि 1 लाख रुपये और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की रिपोर्ट उनके निदेशक मंडलों को शीघ्रतापूर्वक दी ाए।

ऋण वृद्धि 22% तक पहुं ा सकती है

निष्प्रभावी औद्योगिक उत्पादन द्वारा बदतर हालत में पहुं ाी मुद्रास्फीति के कर्षण प्रभाव के बाव ूद वर्ष 2011-12 के दौरान ऋण वृद्धि 22% के अ छे -खासे स्तर पर पहुं ा सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्य-तिमाही समीक्षा में बताया गया है कि वर्षानुवर्ष खाद्येतर ऋण वृद्धि मा र्ा के 21.3% से घट् कर ून के प्रारंभ में 20.6% के स्तर पर आगई, किन्तु वह 19% के सांकेतिक अनुमानों से अधिक स्तर पर कायम रही।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

6

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुख र्ाी ने हाल ही में सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन और ऋण संवितरण रिकार्ड की समीक्षा की है। मंत्रालय ने कृषि ऋण के लिए वर्ष 2010-2011 के दौरान 3.75 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए 4.75 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। वर्ष 2010-11 में कृषि ऋण का वास्तविक संवितरण 46 लाख करोड़ रुपये रहा, ाो लक्ष्य से 19% अधिक था। इसी अवधि के दौरान कुल 5.5 करोड़ कृषि ऋण खातों का वित्तीयन किया गया, ि ाससे कृषि खातों की संख्या में 14.11% की तथा संवितरित ऋणों की रकम में 16.19% की वृद्धि हुई। किसान क्रेडिट कार्ड यो ाना के तहत 31 दिसम्बर, 2010 के दिन बैंकों ने 9.81 करोड़ कार्ड ाारी किए थे। शिक्षा क्षेत्र के लिए सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया ऋण 31 मा र्ा 2011 के दिन 43,074 करोड़ रुपये रहे। 25 मा र्ा, 2011 के दिन आधारभूत सुविधा क्षेत्र को बकाया बैंक ऋण 4.57 लाख रुपये था। कुल मिला कर 72,950 गांवों की पह ाान उपयुक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने तथा उन्हें समग्र बैंकिंग नेटवर्क में लाने के उद्देश्य से की गई। इनमें से 29,569 गांवों को वित्तीय वर्ष 2010-11 में शामिल किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निरुद्ध पारस्परिक निधि यो ानाओं में बैंक निवेशों की सीमा तय की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुन: कहा है कि बैंकों द्वारा पारस्परिक निधियों की एक वर्ष से अनधिक के पोर्टफोलियो की भारित औसत परिपक्वता वाली अनिरुद्ध अथवा अल्पावधिक ऋण यो ानाओं में कुल निवेश पिछले वर्ष के 31 मा र्ा के दिन की उनकी निवल मालियत की 10% की विवेकसंमत सीमा के अध्ययीन होंगे। भारित औसत परिपक्वता की गणना निवेश की गई रकमों द्वारा भारित प्रतिभूतियों की परिपक्वता की शेष ब ाी अवधियों के औसत के रूप में की ाएगी। शीर्ष बैंक ने यह भी कहा है कि सह ा संक्रमण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारस्परिक निधियों की इन यो ानाओं में 10% की सीमा से अधिक

निवेश करने वाले बैंक इन अपेक्षाओं का यथाशीघ्र, किन्तु 5 ुलाई, 20011 से अधिकतम छ: माह में पालन कर सकते हैं।

उ ा बॉण्ड प्रतिफल उधार के लिए खतरा

दुराग्रही उ ा मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई दर वृद्धि के अनुसरण में 1 अप्रैल को प्रारंभ हुए वित्त वर्ष से न्यूनतम 10 वर्षीय बॉण्डों के प्रतिफल में लगभग 40 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। नकदी की कठिन स्थिति और ब .ती दरों पर ि ांता के आधार पर व्यापारियों द्वारा 8.50% के ि ातनी उ ा वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किए ाने के फलस्वरूप प्रतिफल 8.32% और 8.38 % की श्रेणी में ब . रहा है। बॉण्डों के प्रतिफल के "अस्वीकार्य रूप से अधिक" बने रहने पर सरकार को अपने उधार लेने के कार्यक्रम को रद्द अथवा स्थगित करने पर वि ाार करना पड़ सकता है।

7

नये ऋण स्वीकृत करते समय विहित कर्तव्यपरायणता बरतें

अन ार्क आस्तियों में तीव्र उछाल को 'ि ांता का क्षेत्र' बताते हुए वित्त मंत्री श्री प्रणब मुख र्ी ने सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों से नये ऋण स्वीकृत करते समय विहित कर्तव्यपरायणता बरतने के लिए कहा है। उन्होंने सार्व ानिक क्षेत्र के सभी बैंकों को आस्ति की गुणवत्ता में अधोमुखी प्रवृत्ति के प्रति आगाह किया है। बैंकिंग प्रणाली में सकल अन ार्क आस्तियों का स्तर 31 मा र्ा, 2010 के दिन के 59,927 करोड़ रुपये से ब . कर 31 मा र्ा, 2011 के दिन 74,617 करोड़ रुपये पर पहुं ा गया है। वित्त मंत्री ने सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ि ासके माध्यम से अन ार्क आस्तियों की वृद्धि को रोका ा सके।

बैंकरों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से ब ात दरों का अविनियमन स्थगित करने का अनुरोध

वर्तमान अस्थिर वातावरण से परेशान बैंकरों ने ब ात खातों पर दर को अविनियमित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। भारतीय बैंक संघ (IBA) ने उद्योग के रुख से भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत करा दिया है तथा फिलहाल यथास्थिति बनाए रखे ाने का अनुरोध किया है। हालांकि, बैंकों का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब ात खातों पर दर को अविनियमित किए ाने को वरीयता दिए ाने की स्थिति में उन्हें उन सेवाओं पर यथो ि ात रूप से प्रभार लगाने की अनुमति दी ानी ाहिए ो वे लागत रहित प्रदान कर रहे हैं। बैंकों ने यह तर्क दिया है कि ' ूंकि दों में अब ऊर्ध्मुखी संशोधन करते हुए उन्हें 4% कर दिया गया है,, ामाकर्ताओं को इसका प्रतिकर मिल रहा है।

इसके अलावा, ूंकि दर की गणना दैनिक आधार पर की ाती है, इसलिए मुद्रास्फीति और अन्य प्रमुख दरों के सम्बन्ध में कुछ स्तर तक स्थिरता आने तक ब ात दरों को उद्योग के हित में अविनियमित नहीं किया ाना ाहिए।"

लघुतम गृह ऋण समूह में सर्वो ा अन ाक आस्तियां

अधिक मुद्रास्फीति और भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक कठोरता के बाद बैंकों द्वारा ब्या ा दरों में तीव्र वृद्धि ने छोटे उधारकर्ताओं के ऋण ुकाने के सामर्थ्य को प्रभावित कर दिया है। सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन से सम्बन्धित हाल के अध्ययन में सकल अन ाक आस्तियों में गृह ऋणों की ूकों की घटनाओं का योगदान 2 लाख रुपये तक की श्रेणी में सर्वाधिक था। यह आंकड़ा वर्ष 2010-11 में 6% था ाो वर्ष 2009-10 के 6.4% के स्तर से थोड़ा सा अधिक था। भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी का कहना है कि " ूंकि इस श्रेणी के उधारकर्ता अल्प आय वर्ग से सम्बन्धित होते हैं, दरों में वृद्धि से उनकी ुकौती का सामर्थ्य प्रभावित हुआ है।" बैंक का औसत ऋण आकार लगभग 12 लाख रुपये का है।

शैक्षणिक ऋणों से सम्बन्धित सिफारिशें

ऋण गारंटी निधि के सृ ान, ुकौती अवधि के विस्तार और शैक्षणिक ऋणों की अधिस्थगन अवधि में विस्तार भारतीय बैंक संघ द्वारा शैक्षणिक ऋण यो ाना पर गठित विशेषज्ञ समिति की कुछेक सिफारिशें हैं।

बैंक अग्रिमों में 3.75 % की ब ोत्तरी

बैंक अग्रिमों में वृद्धि की प्रवृत्ति भले ही वह 3.75% की दर से ही हो, ारी रही। अप्रैल - ून तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 5% की तुलना में वह 3.75% रही। बैंकों ने वर्ष 2011-12 की 1ली तिमाही में 1.5 लाख करोड़ रुपये संवितरित किए। वर्तमान वित्त वर्ष की 1ली तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में दो श्रृंखलाओं में 75 आधार अंकों की वृद्धि की गई। ऐन् ाल ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (अनुसंधान) वैभव अग्रवाल का कहना है। कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 19% की ऋण वृद्धि का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर बैंक सावधि ामाराशियों पर अधिक ब्या ा दरें प्रदान करके निधियां ुटाने में समर्थ हुए हैं। बैंक ामाराशियां वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5.5 % (अथवा 2.8 लाख करोड़ रुपये) ब ीं। ामाराशियों में एक वर्ष पहले 3.2% का संकु ान आया था। पिछले वर्ष बैंकों ने ऋण की मांग को समर्थन देने के लिए निरुद्ध निधियों में अतिरिक्त निवेश को बे ा दिया था।

वार्षिक आधार पर बैंक ामाराशियों में अप्रैल- ून 2011 वाली तिमाही की शुरूआत में 15.8% की वृद्धि की तुलना में 1 ुलाई को 18.4%की वृद्धि द र्ा हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2011-12 के पूरे वित्त वर्ष के लिए 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया था।

बैंक आधारभूत सुविधा में ऋण ोखिम (exposure) ब .ा सकते हैं

भारतीय साख निर्धारण सू ाना सेवा लिमिटेड (CRISIL) के हाल के एक अध्ययन के अनुसार बैंकों के समक्ष उपस्थित आस्ति-देयता असंतुलन (बेमेल) की समस्या को उनके द्वारा पूं ाी बाज़ारों में अधिकाधिक सहभागिता के द्वारा हल किया ा सकता है। उक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय बैंक आधारभूत सुविधा क्षेत्र को आधारभूत सुविधा परियो ानाओं के ऋणों के ऋण पूं ाी बाज़ारों के माध्यम से पुनर्वित्तीयन के द्वारा उनकी आस्ति-देयता प्रोफाइल को प्रभावित किए बिना उनकी निधीयन क्षमता को अगले पां ा वर्षों में लगभग 20% (1 लाख करोड़ रुपये) तक ब .ा सकते हैं। ऐसा होने के लिए बैंकों को वर्तमान प्रवर्तन करें और धारण करें मॉडेल के स्थान पर निर्माण के स्तर के दौरान प्रवर्तन करें और वहन करें वाला मॉडेल अपनाना ाहिए और उन ऋणों का पुनर्वित्तीयन करना ाहिए ि ानका निवेश संस्तर अपेक्षाकृत लम्बी अवधि वाला हो।
इसके अलावा, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी मूल्य निर्धारण की रणनीति को इस प्रकार विकसित करें कि इस प्रकार ऋण और भी ोखिम-आधारित हों। ब ढ़ हुए मूल्यांकन एवं निगरानी कौशलों के साथ बैंक आधारभूत सुविधा परियो ानाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण

ऋणदाता बने रहेंगे। वे अपनी पूं ाी का उपयोग अधिक विवेकपूर्ण रीति से करेंगे , क्योंकि परियो ाना ऋणों की प्रभावी अवधि पूर्ववर्ती 12-15 वर्षों के ब ाय केवल 3-4 वर्ष ही होगी।

वाणि ियक क्षेत्र में गैर-बैंकिंग निधीयन में वृद्धि

बैंकों के वाणि ियक क्षेत्र के लिए वित्त के प्रमुख स्रोत बने रहने के बाव ूद भारतीय कम्पनियों की गैर-बैंक निधीयन स्रोतों पर निर्भरता ब . रही है। इस वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह में गैर-बैंक स्रोतों का अंश एक वर्ष पहले की अवधि के 36% से ब . कर 49% हो गया। इस अवधि के दौरान भारत और विदेशों, दोनों ही में गैर-बैंकिंग ैनलों से निधीयन में ब .ोत्तरी हुई ।

मंत्रिमंडल ने एसबीआई कॉमर्सियल के मूल कम्पनी भारतीय स्टेट बैंक में विलयन को मं ूरी दी

सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्सियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक (SBICI) के उसके मूल बैंक भारतीय स्टेट बैंक में विलयन को अनुमोदित कर दिया है। दो शाखाओं वाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्सियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी है तथा वह वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं का एक विन्यास उपलब्ध कराने वाले एक नि ाी बैंक के रूप में कार्यरत है।

नियम सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों के कारोबारी लक्ष्य को सार्व ानिक बना सकते हैं

वित्त मंत्रालय (MoF) आगामी वित्त वर्ष से सार्व ानिक क्षेत्र के बैंक ि ास तरीके से अपने कार्य-निष्पादन की यो ाना बनाते हैं उसमें भारी परिवर्तन लाने की यो ाना बना रहा है। आशय विवरण (Sol) की मौ ूदा प्रणाली, ि ासके द्वारा सार्व ानिक क्षेत्र के बैंक अपनी कार्य यो ाना अर्थात् वित्त मंत्रालय के साथ वि ाार विमर्श के बाद विविध कारोबारी मापदंडों के सम्बन्ध में अपने लक्ष्यों के पूर्वानुमान बनाते हैं, के स्थान पर परिणामों की रूपरेखा का दस्तावे ा (RFD) नामक एक नयी व्यवस्था लागू की ाएगी। परिणामों की रूपरेखा के दस्तावे ा के तहत सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त मंत्रालय से वि ाार विमर्श किए बिना स्वयं अपने समग्र दर्शन (vision) का उल्लेख करना होगा। हालांकि, वित्त मंत्रालय के अनुमोदित कर दिए ाने के बाद यह प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया ाएगा। इसीप्रकार, परिणामों की रूपरेखा के दस्तावे ा मे यह अपेक्षित होगा कि बैंक के अंतिम परिणाम 1 मई तक अपलोड कर दिए ाएं। आशय विवरण में बैंक अपने पूर्वानुमानों में अपने आप को एक विशिष्ट वर्ष तक सीमित रखते हैं।

10

बैंकों ने अन ाक आस्तियों की पह ाान करने की प्रणाली अपनाने हेतु समय सीमा ब ़ाने की मांग की

सार्व ानिक क्षेत्र के बैंकों ने सरकार से अन ाक आस्तियों की प्रौद्यिगिकी पर आधारित पह ाान वाली प्रणाली अपनाने की दिशा में प्रस्थान करने की समय सीमा ब ़ाने का अनुरोध किया है। उक्त समय सीमा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली है। विशेष रूप से काफी बड़ी संख्या में छोटे खाते रखने वाले बैंकों ने छ महीने के विस्तार की मांग की है। कोर बैंकिंग समाधान (CBS) के कार्यान्वित हो ाने पर उक्त प्रणाली से शारीरिक हस्तक्षेप किए बिना ही अन ाक आस्तियों का पता ाल ाएगा।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋणों को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणी' से बाहर रखे ाने का ब ाव

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के दावों के प्रतिकूल गैर-बैंकिंग कम्पनियों को दिए ाने वाले बैंक ऋणों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणी से निष्कासन वास्तविक रूप से वास्तविक उधारकर्ता की सस्ते ऋण तक पहुं ा में सहायक सिद्ध होगा। मई में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्णय दिया था कि बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिए ाने वाले ऋण अब उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सम्बन्धी दायित्व को पूरे करने वाले नहीं माने ाएंगे। इसके पीछे निहित वि ाार बैंकों को उन क्षेत्रों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से परोक्ष रूप के ब ााय सीधे उधार देने पर विवश करना था। इससे उन गैर-बैंकिंग कम्पनियों के लिए उधार मंहगे हो गए, ाो इस बात का रोना रोती थीं कि इसके परिणामस्वरूप उनके उधार अपेक्षाकृत अधिक दर वाले हो ाएंगे तथा वास्तविक प्रयोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़ेगा - ाो समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है।

ग्राहक सेवाओं पर पैनल

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा का नवीकरण करने के उपायों की शीघ्र घोषना करने वाला है। ग्राहक सेवाओं पर गहन वि ाार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 4 ुलाई को अपनी रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंप दी है।

रुपये की परिवर्तनीयता

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि "भारत के लिए रुपये की परिवर्तनीयता के लिए अंशांकित दृष्टिकोण अपनाना अवश्यक है। देश के लिए एक स्थिर ालू खाते का अंतर बनाए रखना ारूरी है; हमें बाज़ार द्वारा निर्धारित विनिमय दर की आवश्यकता है।" गवर्नर ने यह भी वि ाार व्यक्त किया है कि देश के पास अनिश्चितताओं के समक्ष पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का होना आवश्यक है। ानवरी-मा र्ा की अवधि में भारत के ालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% था, ाो पिछली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के 2.1% से काफी कम था। यह घाटा पिछली तिमाही के 10 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से तीव्र गति से कम हो कर 45.4

बिलियन अमरीकी डालर रह गया। भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में 6.695 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, ि ससे वह 1 ुलाई को समाप्त सप्ताह में 315.715 बिलियन अमरीकी डालर हो गई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां मई 2008 के अंत में 314.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुं ा गई थीं। विदेशी मुद्रा भंडार की एक प्रमुख घटक, विदेशी मुद्रा आस्तियां भी 6.365 बिलियन अमरीकी डालर ब . कर 1 ुलाई को समाप्त सप्ताह में 283.459 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। डॉ. सुब्बाराव का कहना है, "राष्ट्र वृद्धि को आगे ब .ाने के लिए अकेले सेवा उद्योग पर नहीं निर्भर कर सकता, आर्थिक वृद्धि को आगे ब .ाने के लिए कृषि क्षेत्र को 4% की दर से विस्तार करना होगा। नौकरियां ब .ाने के लिए विनिर्माण पर भी संकेन्द्रण ारूरी है।"

बैंक सेवाएं आवश्यक रूप से सस्ती की ाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवाओं के नवीकरण पर ि ंतन ारी रखे ाने के बाव ूद भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. ाक्रवर्ती विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक प्रभारों को मोबाइल उद्योग के ि ितना ही ग्राहकोनुकूल बनाया ाना ाहते हैं। डॉ. ाक्रवर्ती इस बात पर बल देते हैं कि "विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिए मूल्य-निर्धारण को ग्राहक कितना ुका सकता है इस पर आधारित किया ाना होगा। वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में परिणत करने के लिए हमें उसके लागत आधारित मूल्य-निर्धारण मॉडेल के लिए दूरसं ाार उद्योग का अनुकरण करने की ारूरत है। बैंकिंग ानसामान्य की संवृत्ति केवल तभी बन सकती है, ाब वह ानता के लिए वहनीय हो।"

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक भारतीय रिज़र्व बैंक होगा

सरकार ने सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को भारतीय रिज़र्व बैंक के विस्तार क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव किया है। भारतीय रिज़र्व को वित्त मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्था (विकास और

विनियमन) विधेयक के मसौदे में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में इस क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने और विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया ाएगा। संशोधित विधेयक में भारतीय रिज़र्व बैंक को मार् ािन सम्बन्धी सीमाओं, ऋणों की अवधि, ुकौती कार्यक्रमों की आवधिकता, कार्रवाई शुल्कों की वसूली, वित्तीय सहायता पर अधिकतम वार्षिक प्रतिशत

दर आदि के सम्बन्ध में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मार्गदर्शन करने का अधिकार प्रदान किया ाना प्रस्तावित है।

सूक्ष्म ऋणदाता आय ब ाने के लिए मुख्य व्यवसाय के परे अवसर की तलाश में

आवास वित्त, स्वर्ण ऋणों, मोबाइल वित्तीयन में नये प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हुए सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अब गरीबों को सूक्ष्म उधार देने के मुख्य व्यवसाय से आगे ब ते हुए आय की निरंतर धारा की तलाश में हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के उनके पोर्टफोलियो के 15% तक गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति दिए ाने के फलस्वरूप सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उपर्युक्त नये प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही हैं।

महिला बैंक, स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ऋण

ग्रामीण विकास मंत्री श्री ायराम रमेश ने घोषणा की है कि सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने के अलावा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बैंक उधारों पर ब्या ा दरों को किसानों को फसल ऋणों की दरों के सम स्तर पर लाने की यो ाना बना रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों ही प्रस्तावों पर वित्त मंत्री श्री प्रणब मुख ी के साथ ा ी की ाएगी। पिछले ब ट भाषण में श्री मुख ी ने महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने और उनके स्वयं सहायता समूहों को ब ावा देने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये की मूल पूं ी से 'महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधि' के सृ ान की घोषणा की थी।

विदेशी मुद्रा विनिमय

अगस्त 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी ामाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी ामाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		

अमरीकी डालर	0.760 25	0.6380	0.9350		

अनिवासी विदेशी ामाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.76025	0.638	0.935	1.318	1.718
ीबीपी	1.58781	1.3210	1.5650	1.8580	2.1410
यूरो	2.16938	1.938	2.111	2.308	2.509
ापानी येन	0.55938	0.371	0.395	0.440	0.509
कनाडाई डालर	1.85333	1.645	1.860	2.070	2.270
आस्ट्रेलियाई डालर	5.43750	4.795	4.840	5.065	5.188

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**22 ुलाई 2011 के दिन**	**22 ुलाई 2011 के दिन**
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	**2**	**3**
कुल प्रारक्षित निधियां	14,06, 805	316,,801
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,62, 725	284, ,526
ख) सोना	1, 10, 317	24, 668
ग) विशेष आहरण अधिकार	20, 528	4, 625
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	13, 235	2, 982

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

अंतरराष्ट्रीय समा ाार

यूरोपीय संघ बैंक पूं ाी के सम्बन्ध में अग्रणी

यूरोपीय संघ (EU) 2008 के वित्तीय संकट की किसी भी पुनरावृत्ति से सुरक्षित रहने के प्रयास में

तथाकथित बासेल III दिशानिर्देशों को कानूनी रूप देने की शरूआत करने वाला पहला अधिकार

क्षेत्र बन गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत इन मानकों को बैंकों को अपेक्षाकृत बड़ी और बेहतर पूं ाी रखने में समर्थ बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। पूं ाी आवश्यकता सम्बन्धी निर्देश 4 के रूप में ज्ञात इन प्रस्तावों में सामान्य इक्विटी टियर- I अथवा सीईटी- I के नाम से अभिहित सर्वो ा गुणवत्ता वाली वह पूं ाी, ि ासे बैंकों को अवश्य रखना है, ोखिम-भारित आस्तियों के 2% से ब. कर 4.5% हो ाएगी। सामान्य इक्विटी टियर- I के रूप में किसकी गणना की ा सकती है इसका निर्धारण करने के लिए 14 कठोर मानदंड होंगे। ोखिम-भारित आस्तियों के 2.5% के स्तर तक के श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाली पूं ाी से निर्मित "पूं ाी संरक्षण के सुरक्षित भंडार" की भी व्यवस्था होगी, ि ासे प्रभावी तौर पर यह अनुपात 7% हो ाएगा। बैंकों के इस सुरक्षित भंडार का उल्लंघन करने पर उन्हें उनके द्वारा भुगतान किए ा सकने वाले बोनसों और लाभांशों पर सीमाओं का सामना करना होगा। इसके अलावा उनके द्वारा आवश्यक रूप से रखी ाने वाली न्यूनतर गुणवत्ता वाली पूं ाी आवश्यकता की भी अपेक्षा होगी। इसके भी अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, उन्हें इस बात का भय होने पर किसी क्षेत्र को उधार नियंत्रण से परे हो रहा है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले सुरक्षित भंडारों के समावेश वाले विशेष " प्रति- ाक्रीय सुरक्षित भंडारों" की संकल्पना को भी लागू कर सकते हैं। यो ाना यह है कि नये नियमों को 2013 से लेकर 2018 तक विस्तारित करते हुए यूरोपीय संघ में 8,000 से अधिक बैंकों में लागू किया ाए। ब्रुसेल्स नयी ालनिधि आवश्यकताएं अर्थात् ामाराशियों को आहरित किए ाने से निर्मित अ ाानक मांगों को पूरा करने हेतु नकद आस्तियां लागू करना ाहता है।

अर्थव्यवस्था

ग्रामीण परिवारों के ख ा में वृद्धि शहरी परिवारों के स्तर तक पहुं ाी

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा ारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2009-10 तक के पां ा वर्षों में हुई उ ा आर्थिक वृद्धि ने देश के प्रति परिवार के मासिक उपभोग को पिछले पां ा वर्षों में 2/5 गुना ब.ा दिया है। 2004-05 और 2009-10 की अवधि के बी ा ाब अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 8.7% की दर से वृद्धि हुई, तो ग्रामीण भारतीय परिवारों ने अपने ख ा को लगभग 63% ब.ा दिया, ो 68% से केवल एक टैड, अर्थात् वह दर ि ास पर शहरी परिवारों का व्यय ब.ा, कम है। पिछले वर्षों में ाब सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 6% थी, ग्रामीण और शहरी परिवारों के व्यय में हुई वृद्धि क्रमश: 16% और 29% थी। इस तथ्य कि पिछले दशक में ग्रामीण भारतीयों द्वारा किए गए औसत पारिवारिक व्यय में उनके शहरी प्रतिपक्षियों की तुलना में काफी अधिक ते ाी से वृद्धि हुई से यह पता ालता है कि आर्थिक वृद्धि न केवल अपेक्षाकृत अधिक थी, अपितु वह 2009-10 तक के पां ा वर्षों में अधिक समावेशी भी रही।

वृद्धि को 9.5% अधिक ले ाने पर मुद्रास्फीति ब ेगी

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगरा ान का कहना है कि "12वीं पं ा वर्षीय यो ाना, ाो आगामी वर्ष आरंभ होने वाली है, में वृद्धि को 9.5% से अधिक ले ाने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उ ातर स्फीतिकारी दबाव तथा ालू खाते के घाटे से सम्बन्धित कठिनाई पैदा होगी। " उन्होंने यह भी कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ब ात और निवेश के अनुपातों, ाो क्रमश: 36% और 38% हैं, को अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि में सहायक होना ाहिए। हालांकि, सरकार के लिए वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करते समय रा ाकोषीय दृ ीकरण प्राप्त करने के अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, ालू खाते के घाटे के यथोि ात स्तर का प्रबन्धन करने की अल्पावधिक समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक हो ाता है। आगामी यो ाना अवधि में वृद्धि को स्थिर रखने के लिए स्फीतिकारी दबावों को रोकने के अलावा, कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि तथा बि ाली और आधारभूत सुविधा क्षेत्रों में समग्र आर्थिक वृद्धि से अपेक्षाकृत अधिक की वृद्धि द र्ा करना भी आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'निकट अवधि' वाले मुद्रास्फीति के दबावों के ारी रहने की ोतावनी

इस बात का संकेत देते हुए कि वह ब्या ा दरों में वृद्धि को द तापूर्वक लागू करेगा, भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि मुद्रास्फीति को रोकने के 'अधूरे कार्य' का तकाज़ा है उसके प्रति-स्फीतिकारी मौद्रिक दृष्टिकोण का ारी रहना। कठोर मौद्रिक नीति पर व्यापक ाोर तब तक ारी रहेगा ाब तक कि मुद्रास्फीति के उसकी सहूलियत वाले स्तर पर वापस आ ाने का विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिल ाता। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ोतावनी दी है कि ुलाई -सितम्बर 2011 की अवधि में स्फीतिकारी दबावों के यदि वे गहन नहीं होते, तो उनमें कमी आने के पहले, उनके बने रहने की संभावना है।

खाद्येतर ऋण वृद्धि अधिक बनी रही : भारतीय रिज़र्व बैंक

अपनी 'स्थूल-आर्थिक और मौद्रिक घटनाओं की पहली तिमाही की समीक्षा 2011-12' में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि इस अवधि में सामान्यया दिखाई देने वाली मौसमी मंदी के विपरीत इस वित्त वर्ष में अब तक गिरावट के बाव ूद खाद्येतर ऋण वृद्धि की दर उ ा बनी रही। ऋण वृद्धि, ि ासमें 2010-11 की पहली तिमाही के दौरान तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई थी, वर्षानुवर्ष आधार पर आंशिक रूप से अपेक्षाकृत उ ातर उधार दरों से सं ारण का प्रतिबिंबन करते हुए और आंशिक रूप से आधार प्रभाव के कारण 2011-12 की पहली तिमाही में कम हो गई।

उत्पाद एवं गंठ ाोड़

संगठन	ि ास संगठन के साथ गंठ ाोड़ हुआ	उद्देश्य
इंडसइंड बैंक	भारतीय थल सेना	भारतीय थल सेना के सभी श्रेणी के कार्मिकों को वेतन खाते ाारी करने हेतु सम ौता ज्ञापन।
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	टाइम्स ऑफ मनी	22 देशों में स्थित सभी अनिवासी भारतीयों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) / तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के नेटवर्क के अधीन भारत में किसी भी बैंक को ऑनलाइन निधियां विप्रेषित करने में समर्थ बनाना।

नयी नियुक्तियां

श्री हारुन राशिद खान भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर नियुक्त किए गए हैं।

श्री मोहन वसंत टंसाले सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

श्री ाी. पद्मनाभन भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किए गए हैं।

कोटक महिन्द्रा बैंक की एक सहायक कम्पनी कोटक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने सुश्री शेफाली शाह को वरिष्ठ कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री अर्णब राय ने राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

सुश्री उषा अनंतसुब्रमणियन ने पं ााब नैशनल बैंक (PNB) की कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

"विज़न" के पिछले अंकों में हमने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के इतिहास, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) , उसके गठन एवं संगठन के सम्बन्ध में सू ाना प्रदान की थी तथा हाल के

अंक में हमने मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की भूमिका को वर्णित करने का प्रयास किया था। हमारी इ छा है बैंकरों को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अब तक अत्यधिक सुज्ञात नही तथ्यों से परि ित कराना। हम आशा करते हैं कि उपलब्ध कराई ा रही सू ाना हमारे पाठकों की रु ा के अनुरूप है। हम अपने पाठकों से अपने प्रयासों के बारे में बहुमूल्य प्रति-सू ाना आमंत्रित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के सम्बन्ध में सू ाना उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों को ाारी रखते हुए हम वर्तमान अंक में पिछले पां ा वर्षों के दौरान वैश्विक वित्तीय संकटों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की पहलकदमियों की सू ी प्रस्तुत कर रहे हैं:

वित्तीय संकट पर बासेल समिति की अनुक्रिया

30 ानवरी 2006	बासेल II : पूं ी मापन और पूं ी मानकों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण: एक संशोधित ं ाा - व्यापक संस्करण
12 अक्तूबर 2007	व्यापार बही में अंतरराष्ट्रीय ूक ोखिम के लिए पूं ी परिकलन हेतु दिशानिर्देश - परामर्शी दस्तावेज़
25 सितम्बर 2007	वैश्विक बैंक पर्यवेक्षकों ने ालनिधि ोखिम प्रबन्धन और पर्यवेक्षण की सुदृ. विवेकपूर्ण प्रथा के मानकों की पुष्टि की
20 नवम्बर 2008	बैंकिंग संकट के सबकों से निपटने के लिए बासेल समिति द्वारा घोषित व्यापक रणनीति
12 मा ि 2009	बासेल समिति द्वारा घोषित पूं ी पर पहलकदमी
30 मा ि 2009	संकट के प्रत्युत्तर में बासेल समिति द्वारा पहलकदमी
अप्रैल 2009	बैंकों के वित्तीय लिखतों से सम्बन्धित उ ित मूल्य वाली प्रथाओं के आकलन के लिए पर्यवेक्षी मार्गदर्शन - अंतिम दस्तावे ा
मई 2009	विवेकपूर्ण दबाव परीक्षण प्रथाओं के पर्यवेक्षण के सिद्धांत - अंतिम दस्तावेज़
13 ुलाई 2009	बासेल समिति द्वारा बासेल II पूं ी ा ो में वृद्धियों की घोषणा की गई
27 अगस्त 2009	वित्तीय संस्थाओं के लिए बासेल समिति द्वारा लेखांकन मानकों के संशोधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत ाारी किए गए
7 सितम्बर 2009	वैश्विक बैंकिंग संकट पर व्यापक अनुक्रिया.

15 अक्तूबर 2009	बासेल समिति द्वारा व्यापार बही के मात्रात्मक प्रभाव का अध्ययन : परिणाम
17 दिसम्बर 2009	बैंकिंग क्षेत्र के ल ाीलेपन का सुदृ ़ीकरण -परामर्शी दस्तावेज़
17 दिसम्बर 2009	ालनिधि ोखिम प्रबन्धन, मानकों एवं निगरानी की अंतरराष्ट्रीय रूपरेखा -परामर्शी दस्तावेज़

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी ाानकारी

अनुरूप (match) दर वाली निधियां

ाब किसी ऋण की ब्या ा दर ऋण के रूप में दी गई निधियों के स्रोत पर ब्या ा दर के अनुरूप (अथवा उसके अत्यंत निकट) हो। इसका एक उदाहरण होगा यदि किसी बैंक ने 100,000 अमरीकी डालर की ामाराशि स्वीकार की हो तथा उस पर पां ा वर्ष के लिए 5% ब्या ा देने पर सहमत हुआ हो, उसके बाद 100,000 अमरीकी डालर 5.25% पर उधार दे दिया हो। प्रतिभूतिकरण उधारदाता अनुरूप दर वाली निधियों का विशिष्ट प्रयोक्ता होगा। अनुरूप-दर वाली निधियां समय-पूर्व ुकौती पर अत्यधिक उ ा दंडस्वरूप शुल्क वसूल करती हैं, क्योंकि मध्यवर्ती ने ामाकर्ता को विशिष्ट ब्या ा दर का भुगतान करने की सहमति व्यक्त की है। यदि ाकौती हतोत्साहित नहीं की ााती, तो मध्यवर्ती को उसे ब्या ा का भुगतान मिलना बंद हो ााने पर ब्या ा का भुगतान करना पड़ सकता है।

शब्दावली

परिणाम की रूपरेखा वाला दस्तावेज़ (RFD)

परिणाम की रूपरेखा वाला दस्तावेज़ (RFD) अनिवार्य रूप से ानता के ानादेश का निरूपण करने वाले किसी मंत्री और इस ानादेश को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी किसी विभाग के सा ाव के बी ा सम ा का रिकार्ड होता है। इस दस्तावेज़ में न केवल सहमत उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियो ानाओं, अपितु उन्हें कार्यान्वित करने में हुई प्रगति को मापने के लिए सफलता के संकेतकोंऔर लक्ष्यों का भी समावेश होता है। सहमत कार्रवाइयों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिणाम की रूपरेखा वाले दस्तावेज़ (RFD) में आवश्यक परि ालनात्मक स्वायत्तता को भी शामिल किया ा सकता है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेन्टर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण की गतिविधियां

- संस्थान द्वारा अपने लीडरशिप सेन्टर, कोहिनूर सिटी, कुर्ला में (इ ि ाप्ट से आए हुए एक दल के लिए 25 ुलाई से 29 ुलाई 2011 तक लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्तीयन पर) एक पां ा दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयो ान किया गया। उक्त कार्यक्रम में इ ि ाप्ट से

आए हुए 12 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस केन्द्र में आयोि ात होने वाला यह इस प्रकार
का दूसरा कार्यक्रम है।

- संस्थान ने आस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैने ामेंट, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया के सहयोग से 29 अगस्त, 2011 से एक के बाद दूसरे दो 3 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम की घोषणा की है। अधिक ाानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

- भारत के समा ाार पत्र पं ाीकार (रि ास्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पं ाीकृत पं ाीकरण संख्या : एमए ा / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
- मुंबई पत्रिका ौनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान समा ाार

परियो ाना वित्त

संस्थान आईएफएमआर, ेन्नै के सहयोग से परियो ाना वित्त में 15वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयो ान कर रहा है। बै ा के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 21 अगस्त से 27 अगस्त 2011 तक आयोि ात होगा। अधिक ाानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

सूक्ष्म / सूक्ष्म शोध

संस्थान द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए सूक्ष्म / स्थूल शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए ाते हैं। अधिक ानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

5वां आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान

5वां आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान 07-09-2011 को सायं 5.30 ब े भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एन. बाघुल द्वारा दिया ाएगा।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
02/07/11 04/07/11 09/07/11 12/07/11 15/07/11 19/07/11 20/07/11
23/07/11 25/07/11 27/07/11 29/07/11

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, ुलाई, 2011

- माह के प्रारंभ में ालनिधि ीली बनी रही, क्योंकि बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की एक दिवसीय पुनर्खरीद खिड़की से ालनिधि समायो ान सुविधा के माध्यम से 1,02,090 करोड़ रुपये उधार लिए।
  मांग दरें भी 7.75% से आरंभ होने के बाद घट कर 4% रह गईं।
- माह के प्रारंभ में ालनिधि की स्थिति सह ा रही, ाबकि अंतिम सप्ताह में 27 ुलाई को हुई अ ानक
  वृद्धि के फलस्वरूप मांग दरों में वृद्धि परिलक्षित हुई।
- दरें 6.47 और 8.02 के बी ा घटती-ब ती रहीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- ून में समाप्त तिमाही में स्थानीय शेयरों के घिसटने के कारण रुपया सीधे तीन तिमाहियों में वृद्धि के बाद
  कम ोर पड़ा।
- विश्लेषकों के अनुसार, हाल के सकारात्मक कारकों के बाव ूद अमेरिका द्वारा क्यूई2 की समाप्ति, आयातित
  मुद्रास्फीति, खगोलीय रूप से अधिक घाटें और विदेशी ऋण; विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत
  निवेशक प्रवाहों में समग्र गिरावट रुपये में किसी और मूल्यवृद्धि को अत्यधिक कठिन बना देंगे और 44.50
  रुपये का समर्थन स्तर होगा।
- सोमवार, 25वीं को स्थानीय तेल आयातकों से यूरो और डालर की ब ी हुई मांग से प्रभावित हो कर रुपया
  उस समय औंधे मुह लु क गया , ाब अधिकांश व्यापारियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत समीक्षा के
  एक दिन पहले प्रतीक्षा करना ही उ ित सम ा ।
- 28वीं को रुपया अमेरिका, ाहां फेडरल रिज़र्व नीतिगत दरों को शून्यवत रखे हुए है, की तुलना में उ ातर
  ब्या ा दरों के कारण निधि प्रवाहों में वृद्धि की आशा में अमरीकी डालर के समक्ष लगभग तीन वर्ष के सर्वो ा
  स्तर तक ब गया।
- यूरो क्षेत्र के ऋण से सम्बन्धित ंिताओं के पुन: उठ खड़ी होने के कारण 29 वीं को यूरो की गिरावट से
  घिसट कर रुपया लु का,, किन्तु अंतर्वाहों के सुदृ होने के कारण वह लगातार दूसरे माह में वृद्धि द र्ा
  करने में कामयाब रहा।

- माह के दौरान ापानी येन और स्टर्लिंग के समक्ष रुपये में मामूली सी गिरावट के संकेत दिखाई पडे।

बम्बई शेयर बाज़ार सू ाकांक

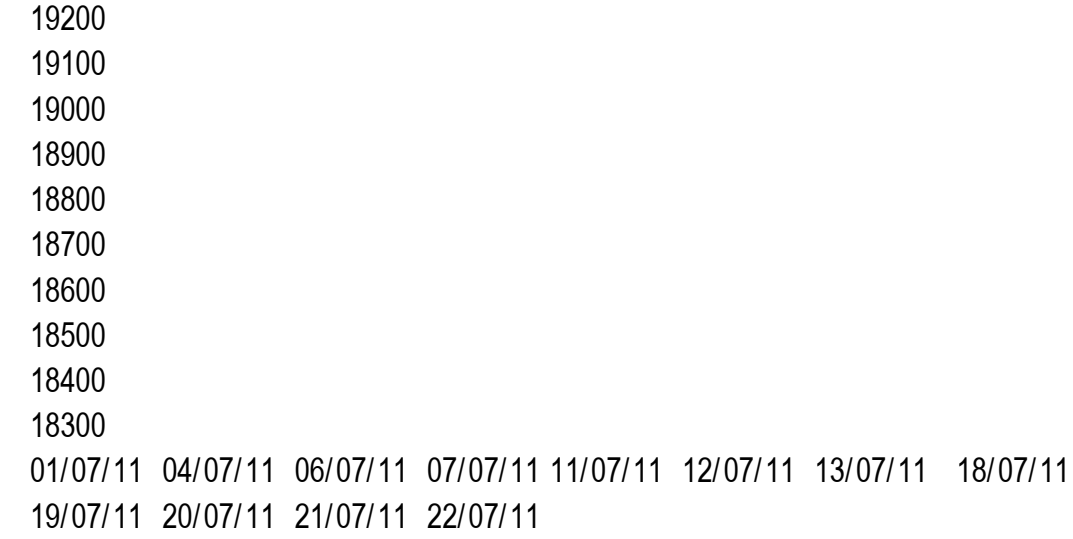

19200
19100
19000
18900
18800
18700
18600
18500
18400
18300
01/07/11 04/07/11 06/07/11 07/07/11 11/07/11 12/07/11 13/07/11 18/07/11
19/07/11 20/07/11 21/07/11 22/07/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंि ाल, डॉ. ई. मो ेास मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंि ाल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंि ाल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अगस्त, 2011